

प्रसाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II--- खण्ड 3--- उपलण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

माधिकार से प्रकारित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं 16] नई दिल्ली, मंगलबार, जनवरी 30, 1968/माघ 10, 1889

No. 16] NEW DELHI, TUESDAY, JANUARY 30, 1968/MAGHA 10, 1889

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या की जाती है जिससे कि यह झलग संकलन के रूप में रका जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF FOOD, AGRICULTURE, COMMUNITY DEVELOPMENT AND CO-OPERATION

(Department of Agriculture)

Land Acquisition Review Committee

The following translation in Hindi of the Land Acquisition (Companies) Rules, 1963 is hereby published under the authority of the President and shall be deemed to be the authoritative text thereof in Hindi under clause (b) of Sub-section (1) of Section 5 of the Official Languages Act, 1963 (19 of 1963).

SARAN SINGH, Jt. Secy.

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास और सहकार मंत्रालय

(कृषि विभाग)

तैंड एक्वोजीशन (कंपनीज) रुत्स, 1963 का हिन्दी में निन्मलिखित श्रनुवाद राष्ट्रपति क ग्राधिकार के अधीन एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है श्रीर राजभाषा श्रिधिनियम, 1963 (1963 का 19) की धारा 5 की उपधारा (1) के खंड (ख) के श्रधीन हिन्दी में उनका प्रमा-णिक पा समझा जाएगा।

नई दिल्ली, 22 जून, 1963

सा • का • निं • 2 34—मू मि श्रर्जन श्रिधिनियम, 1894 (1894 का श्रिधिनियम सं • 1) की धारा \$5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकारों के तथा केन्द्रीय सरकार के श्रौर राज्य सरकारों के श्राफिसरों के मार्गदर्शन के लिये निम्नलिखित नियम एतद्वारा बनाती है, श्रर्थात :—

- 1— संक्षिप्त नाम झौर लागू होना (1) ये नियम भूमि झर्जन (कम्पनियां) नियम, 1963 कहे जा सकोंगे।
- (2) ये नियम श्रिधिनियम के भाग 7 के श्रिधीन सब कम्पनियों के लिये भूमि के श्रिजन को लागू होंगे।
 - 2 परिभाषएं इन नियमों में --
 - (i) "श्रधिनियम" से भूमि श्रर्जन अधिनियम, 1894 (1894 का अधिनियम सं॰ 1) श्रमिशेत है, और
 - (ii) "समिति" से नियम 3 के अधीन गठित भूमि अर्जन समिति श्रभिप्रेत है।
- 3. भूमि अर्जन समिति—(1) श्रिधिनियम के भाग 7 के अधीन भूमि के अर्जन के सम्बन्ध में समुचित सरकार को सलाह देने के प्रयोजन के लिये, समुचित सरकार, शासकीय राजपत में श्रिधि- सूचना द्वारा एक समिति गठित करेगी जो भूमि अर्जन समिति कहलायेगी।
 - (2) समिति में निम्नलिखित होंगे,---
 - (i) राजस्व, कृषि श्रौर उद्योग के विभागों के सरकार के सम्वित या उक्त हर एक विभाग के ऐसे श्रन्थ आफिसर जिन्हें समुचित सरकार नियुक्त करे;श्रौर
 - (ii) ऐसे अन्य सदस्य जिन्हें समुचित सरकार नियुक्त करे, ऐसी अविधि के लिये, जिसे अह सरकार आदेश द्वारा विनिर्दिष्ट करे।
- (3) समुजित सरकार सिमिति के सदस्यों में से एक को उसका सभापति होने के लिये नियुक्त करेगी।
 - (4) समिति प्रानी प्रिक्षिया स्वयं विनियमित करेगी।
- (5) अधिनियम के भाग 7 के अधीन भूमि के अर्जन से सम्बन्ध और उद्भूत होने वाले सब मामलों पर, जिंन पर उससे परामर्श किया जाए, समुक्ति सरकार को सलाह देना और उस तारीबा से जिसको उससे परामर्श किया जाए एक मास के भीतर अपनी सलाह निविद्य करना, समिति का कर्त्तव्य होगा।

परं**शुं** समुचित सरकार, समिति द्वारा इस निमित्त प्रार्थना किए जाने पर भ्रौर प्रयोद्त कारणों के लिये, उनत कालावधि का विस्तार दो मास से भ्रनधिक की भ्रतिरिगत कलावधि के लिए कर तकेगी।

- 4— आर्जन कार्यवाही आरम्भ करने से पूर्व कुछ मामलों की बाबत समुखित सरकार का तमाधान किया जाना.—(1) जब कभी कोई कम्पनी किसी भूमि के अर्जन के लिये समुचित सरकार को आवेदन करे, वह सरकार कलनटर को निदेश देगी कि वह उसे निम्नलिखित मामलों पर रिपीर्ट प्रस्तुत करे, अर्थात्
 - (i) कि कर्राति उत्तवरिक्षेत्र में श्रार्गन के प्रयोजन के लिये उपयुक्त भूमियों का पता लगाने के लिए श्राप्ता को तम प्रयत्न किया है
 - (ii) कि कम्पनी ने हितबद्ध व्यक्तियों से बातचीत करके ऐसी भूमियों की, युक्तियुक्त कीमत का संदाय करके प्राप्त करने के सब युक्तियुक्त प्रयत्न किए हैं ग्रीर ऐसे प्रयत्न ग्रासफल हुए हैं;
 - (iii) कि प्राणित की जाने के लिए प्रस्थापित भूमि उस प्रयोजन के लिये उपयुक्त है;
 - (iv) कि मर्जित की जाने के लिए प्रस्थापित भूमि का क्षेत्र म्रत्यधिक नहीं है;
 - (v) कि कम्पनी भूमि को शीघ्र उपयोग में लाने की स्थिति में है; श्रौर
 - (VI) जहां झर्जित की जाने के लिये प्रस्थापित भूमि झर्छी कृषि-भूमि हो बहा उस भूमि को झर्जन से बचाने के लिये कोई म्रानुकल्पिक उपयुक्त झास्थान नहीं मिल सकता।
- (2) कलक्टर कम्पनी को इस निमित्त कोई भिभिनेदन करने का युक्तियुक्त श्रवसर देने के पश्चात्, उन मामलों की जो उपनियम (1) में निर्दिष्ट है, जांच करेगा श्रीर ऐसी जांच करते समय, बह—
 - (i) ऐसी किसी दशा में जिसमें कि प्रशिंत की जाने के लिए प्रस्थापित भूमि कृषि-भूमि
 हो, जिले के ज्येष्ट कृषिक श्राफिसर से परामर्श करेगा, चाहे ऐसी भूमि श्रष्टिश कृषि≞भूमि हो या न हो,
 - (ii) श्रिश्वित्यम की धारा 23 श्रीर 24 के उपबन्धों को ध्यान में रखते हुए प्रतिकर की लगभग रकम श्रवक्षारित करेगा जिसका उस भूमि के सम्बन्ध में संदेय होना सम्भाव्य है जो कि कलक्टर की राय में कम्पनी के लिये श्रीजित की जानी वाहिए: श्रीर
 - (iii) यह अभिनिश्चित करेगा कि क्या कम्पनी ने अजित की जाते के लिए प्रस्थापित भूमि में हितबद्ध व्यक्तियों को युक्तियुक्त कीमत (जो ऐसे अवधारित प्रतिकर से कम न हो) प्रस्थापित की।
 - स्पव्टीकरण—इस नियम के प्रयोजन के लिये, ''श्रव्ही कृषि-भूमि' से कोई ऐसी भूमि श्रमिप्रेत है जो उसक्षेत्र के जिसमें वह ग्रवस्थित हो, कृषि-उत्पादन के स्तर श्रीर फसल के पैटर्न पर विचार करते हुए, श्रौसत या श्रौसत से श्रधिक ।उत्पादिता वाली है श्रौर उद्यान-भूमि या बाग-भूमि इसके श्रन्तर्गत श्राती है।
- (3) उपनिश्वम (2) के श्रधीन जांच करने के पश्चात् यंथाशंक्यशी झं कलक्टर समुचित सरकार को एक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा और उस सरकार द्वारा उसकी एक प्रति समिति को भेजी जाएगी।•

- (4) समुचित सरकार द्वारा अधिनियम की धारा 6 के अधीन कोई घोषणा तब तक नहीं की आएगी जब तक कि---
 - (i) समुचित सरकार ने समिति से परामर्श न कर लिया हो श्रौर इस नियम के श्रश्चीन निवेदित की गई रिपोर्ट पर श्रौर श्रश्चिनियम की धारा 5 क के श्रश्चीन यदि कोई रिपोर्ट निवेदित की गई हो तो उस पर विचार न कर लिया हो, श्रौर
 - (ii) श्रिधिनियम की धारा 41 के श्रिधीन करार कम्पनी द्वारा निष्पादित न कर दिया गया ही।
- 5—**-बारा** 41 के मानीन करार में उपबन्धित की जाने वाली वार्षे (1) श्रधिनियम की धारा 41 में निर्दिष्ट करार के निबन्धनों के मानर्गत निम्नलिखित बातें होंगी, श्रथाँत्—
 - (i) कि कम्पनी भूमि का प्रयोग, किसी ऐसे प्रयोजन के लिये जो उससे भिन्न हो जिस के लिए भूमि ऋजित की गई है, समुजित सरकार की पूर्व मंजूरी के सिवाय नहीं करेगी:
 - (ii) कि वह समय, जिसके प्रादर निवासगहों या प्रत्यक्षतः तरसंसक्त सुख-सुविधान्नों का परिनिर्माण या उपबन्ध प्रयंवा निर्माण या संकर्म का सिन्नमीण या निष्पादन किया जाएगा, कम्पनी को भूमि के प्रन्तरण की तारीख से तीन वर्ष से प्रधिक नहीं होगा:
 - (iii) कि जहां समुचित सरकार का, ऐसी जांच के पश्चात् जिसे वह प्रावश्यक समझे समाधान हो जाता है कि कम्पनी निवासगृष्ठों या सुख-सुविधामों प्रथवा किसी निर्माण या सकर्म का परिनिर्माण, उपबन्ध, सिन्नमीण या निष्पादन करार में विनिर्दिष्ट समय के अन्दर करने से ऐसे कारणों से निवारित हो गई थी जो उसके नियलण के बाहर थे, वहां समुचित सरकार तत्प्रयोजनार्थ समय का विस्तार ऐसी फालावधि से जो किसी एक समय पर एक वर्ष से अधिक न हो, इस प्रकार कर सकेगी कि विस्तार की कुल कालावधि तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी;
 - (iv) कि यदि कम्पनी करार में उपवन्धित गतों में से किसी का भंग करे, तो समुचित सरकार कम्पनी की भूमि का अन्तरण वा तिल और भून्य घोषित करने वाला, जिस से कि भूमि समुचित सरकार को प्रतिवर्तित हो जाएगी, और यह निदिष्ट करने वाला आदेश दे सकेगी कि अधिनियम की धारा 41 के खण्ड (1) के अधीन अजन के खर्च के रूप में समुचित सरकार को कम्पनी द्वारा सदत रक्तम की एक चौथाई से अनिधिक रक्तम नुकसानी के रूप में समुचित सरकार को सम्पहृत कर दी जाएगी और अतिशेष कम्पनी को वापस कर दिया जाएगा और ऐसे दिया गया आदश अन्तिम और आवदकर होगा;
 - (v) कि यदि कम्पनी भूमि का भाग मान्न उस प्रयोजन के लिए उपयोग में लाती है जिसके लिए वह प्रजित की गई थी भौर समुचित सरकार का समाधान हो जाता है कि यदि उसका उपयोग में न लाया गया भाग पुनगृहीत कर लिया जाए, तब भी कम्पनी भ्रयके द्वारा उपयोग में लाए गए भूमि के भाग का उपयोग जारी रख सकती है तो समुचित सरकार एक आदेश कर सकेगी जिसमें यह घोषणा हो कि भिम का

उसके उपयोग में न लाए गए भाग की बाबत अन्तरण बालित और शून्य है जिस पर ऐसे उपयोग में न लागा गया भाग समुचित सरकार को प्रतिवृत्तित हो जाएगा, और यह आदेश हो कि अधिनयम की धारा 41 के खण्ड (i) के अधिन अर्जन के खर्च के रूप में कम्पनी द्वारा सदत रकम के ऐसे भाग की, जो कि उपयोग में न लाए गए भाग से सम्बन्धित माना जा सकता है, एक चौथाई से अन्धिक रकम नुकसानी के रूप में समृचित सरकार को समपहृत हो जाएगी और उस भाग का अतिशेष कम्पनी को वापस कर दिया जाएगा और ऐसे दिया गया आदेश, खण्ड (vi) के उपबन्धों के अध्यधीन, अन्तिम और आवदकार होगा।

- (vi) कि जहां भूमि के उपयोग में न लाए गए भाग से सम्बद्ध की जा सकते वाली रकम के बारे में कोई विवाद हो, वहां ऐसा विवाद उस न्यायालय को निर्दिष्ट किया जाएगा जिसकी ग्रधिकारिता के भीतर भूमि या उसका कोई भाग ग्रवस्थित है और उस पर उस न्यायालय का विनिश्चय ग्रंतिम होगा।
- (2) जहां कम्पनी करार के निबन्धनों में से किसी का भंग करती है, वहां समृचित सरकार, उपनियम (1) के खण्ड (iv) या खण्ड (v) के अधीन आदेश तब तक नहीं देगी, जब तक कि कम्पनी को उस मामले में सुने जाने का अवसर न दिया गया हो।
- (3) समुचित सरकार, उपनियम (1) के खण्ड (i) के प्रधीन कोई मंजूरी देने या खंड (iii) के ग्रधीन समय का विस्तार करने या उस उपनियम के खंड (iv) या खण्ड (v) के ग्रधीन कोई ग्रादेश देने से पूर्व, समिति से परामर्श करेगी।

6. ग्रतिरिक्त बातें जो धारा 41 के भवीन करार में उपविश्वित की जा सकेगी--

(1) "नियम 5 के उपबन्धों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना श्रधिनियम की धारा 41 में निविद्य करार के उपबन्धों के अन्तर्गत निम्नलिखित बातें भी हो सकेंगी, श्रथीत्—

"कि म्रात्ययिकता के किसी मामले में जहां म्रधिनियम की धारा 11 के म्रधीन भ्रधि-निर्णय दिए जाने से पूर्व धारा 17 के म्रधीन किसी भूमि का कब्जा लेने की प्रास्थपना है, वहां कम्पनी (नियम 4 के उपनियम (2) के खड़ () के म्रधीन भूमि की बाबत यथा ग्रवधारित संदेय प्रतिकर की लगभग रकम के दी तिहाई से ग्रनधिक) ऐसी रकम और ऐसे समय के भीतर जो कलक्टर इस निमित्त विनिधिष्ट करना ठीक समझे ब्याज से मुक्त कलक्टर के पास निक्षिष्त करेगी।"

- (2) जहां उपनियम (1) के अधीन कोई रकम कलक्टर के पास निक्षिष्त की गई हो, वहां कलक्टर ऐसे निक्षिप्त की गई रकम का संदाय उन हितबढ़ व्यक्तियों को निविवस करेगा, जो कलक्टर की राय में अधिनियम की धारा 31 की उपधारा (1) के अधीन प्रतिकर का संदाय प्राप्त करने के हकदार हैं, और जब लक् कि अधिनियम की धारा 31 की उपधारा (2) में विणित आकस्मिकताओं में से किसी एक या अधिक द्वारा निवारित न हो, उसे उन्हें निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन देगा, अर्थात्—
 - (i) हर एक प्राप्तिकर्ता द्वारा इस करार का निष्पादन कि उस द्वारा प्राप्त की गई रकम श्रांतम रूप से प्रधिनिर्णीत प्रतिकर के प्रति समायोजित की जायगी भौर कि जहां उस द्वारा प्राप्त रकम भंतिम रूप से प्रधिनिर्णीत प्रतिकर की रकम से प्रधिक हो, वहां प्रधिक रकम उस से भराजस्थ के बाकाया के रूप में वसूलीय होगी भौर कि वह इस उपनियम के प्रधीन प्रपने द्वारा प्राप्त रकम की बाबल ग्राधिनियम के उपबन्धों के ग्रांधीन किसी व्याज के लिए दादा नहीं करेगा, ग्रीर

- (ii) हर एक प्राप्तिकर्ता द्वारा प्रतिभूति के सहित या रहित जैसा कि कलक्टर विनिध्वत करे एक बन्धपत्न का निष्पादन जिसमें कि प्रतिकर या उसके भाग के लिए किसी ग्रन्य व्यक्ति द्वारा किसी बावे के खिलाफ समुचित सरकार की क्षतिपूर्ति करने का वचनबद्ध हो।
- (3) यधि उपनियम (1) के प्रधीन कम्पनी द्वारा निक्षिप्त की गई रक्षम या उसका कोई भाग उपनियम (2) के प्रधीन संदत न किया जाए, तो कलक्टर यथासाध्यशी घंता से उसे कम्पनी को वापस कर देगा।
- 7. कालिक रिपोटों का निवेदित किया जाना यह सुनिश्चित करने के प्रयोजन के लिए कि कम्पनी द्वारा निष्पादित करार में उपबन्धित मतों का प्रनृपालन किया जाता है, समुचित सरकार कलक्टर को या ऐ से प्रन्य श्राफिसर को, जिसे वह सरकार तत्प्रयोजनार्थ नियुक्त करे, निवेश दे सकेगी कि वह उन मतों को जिनका अनुपालन किया गया हो या न किया गया हो तथा उन कार्यवाद्यों को जो कम्पनी द्वारा उनके अनुपालन के प्रति की गई हों, उपदिश्वित करने वाली एक कालिक रिपोर्ट, ऐसे समय के अन्तरालों पर जो वह विनिदिष्ट करे उसे और समिति को निवेदित करे।
- 8. ज्ञातें जिनके प्रधीन भूमि के अन्तरण के लिये मंजूरी दी जा सकेगी.—जहां कि कोई कम्पनी जिजके लिए भूमि प्रधिनियम के श्रधीन श्रिजित की गई हो उस भूमि या उसके किसी भागके विकय, दान, पट्टे द्वारा या प्रन्यथा श्रन्तरण के लिए समुचित सरकार की पूर्व मंजूरी के लिए श्राबंदन करें, वहां ऐसी कोई मंजूरी तब तक नहीं दी जाएगी जब तक कि ——
 - (i) निवासपृहों, सुख-सुविधान्नों, निर्माणों या सकर्म सहित, यदि कोई हों, भूमि का प्रस्थापित श्रन्तरण किसी श्रन्य कम्पनी को न हो या जहां कम्पनी कोई सहकारी सोसाइटी है वहां ऐसा अन्तरण इसके किसी सदस्य या सभी सदस्यों को न हो, ग्रमका
 - (ii) जहां भूमि कम्पनी द्वारा नियोजित कर्मकारों के लिए निवास गृहों के परिनिर्माण के लिए ही प्रजित की गई हो, वहां निवासगृहों सहित,यदि कोई हों, भूमि का अन्दर्श एसे कर्मकारों को या उनके आश्वित वारिसों को न हो ;

परन्तु ऐसी कोई मंजूरी देने से पूर्व, समुचित सरकार समिति से परामर्श करेगी।

- 9. कुछ कम्पनियों के सम्बन्ध में विशेष उपजन्ध--(1) जब कि केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन या नियंत्रण धीन कम्पनी से भिन्न किसी कम्पनी द्वारा किसी भूमि के अर्जन के लिए समुचित सरकार को आवेषन किया जाए, तो ऐसा अर्जन मामूली तौर से अधिनियम के भाग 7 के उपबन्धों के अनुसार किया जाएगा।
- (2) जहां कि केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार के स्वामिस्वाधीन या नियंद्वणधीन कम्पनी से भिन्न किसी कम्पनी के लिए किसी भूमि को प्राणित करने की प्रस्थापना है, बहुं समुधित सरकार को प्रधिनियम की धारा 17 के प्रधीन प्रदत्त शक्तियां तब तक प्रयोक्तव्य नहीं होंगी जब तक उसका समाधान न हो जाए कि ऐसा करना जीवन या सम्पति को खतरे से बचाने के लिए धावक्यक है या वैसा करना प्रत्या लोकहित में भावश्यक है।
- 10. निरसन-श्रिधिनियम के भाग 7 के श्रधीन, कम्पिनयों के लिए भूमि के श्रर्जन की बाबत श्रपने श्राफिसरों के मार्गधर्मन के लिए समुचित सरकार द्वारा बनाए गए और इन नियमों के प्रारम्म से श्रव्यवहित पूर्ण प्रवृत सब नियम बहुां तक जहां तक कि वे विषय हों, प्रभावी नहीं रहेंग ।

शरएसिंह, संयुक्त सचित ।